



174-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024 (KARTIKA 17, 1946 SAKA)

The 8th November, 2024

Bill No. 19-HLA of 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

- | | | | |
|------------------|--|---|---|
| <p>1.</p> | <p>(1)</p> | <p>This Act may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Act, 2024.</p> | <p>Short title and commencement.</p> |
| | <p>(2)</p> | <p>It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th October, 2024.</p> | |
| <p>2.</p> | <p>In sub-section (1) of section 46 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014,-</p> | | <p>Amendment of section 46 of Haryana Act 22 of 2014.</p> |
| | <p>(I)</p> | <p>for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
“(i) is or at the time of his retirement or resignation was a Judge of the High Court or a District Judge not having less than ten years standing on his superannuation;”;</p> | |
| | <p>(II)</p> | <p>for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-
“(iv) the Chairman shall be a Judge of High Court, if so appointed, and if a Judge of the High Court is not appointed, then the District Judge if so appointed and if the District Judge is also not appointed, then one of the three selected members of the Commission shall be the Chairman in the order of their seniority either in service or at Bar, as the case may be, and the term of the Chairman or the Member shall be five years from the date he assumes charge.”.</p> | |

Repeal and
savings.

3. (1) The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 7 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014 was enacted by the State Government with the objective of providing for autonomous management and effective supervision of Sikh Gurdwaras and Gurdwara Property in the State of Haryana. Section 46 of the said Act provides for constitution of Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission consisting of three members and the Chairman shall be a District Judge, if so appointed and if a District Judge is not appointed than one of the three members shall be the Chairman in the order of their seniority. The term of the Chairman or the Member shall be five years or the age of 65 years whichever is earlier. The Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission is a quasi-judicial authority, whose decisions are final. The dispute relating to the Gurdwara property, its funds and any other disputes between the Gurdwara Committee, Executive Board or any other institutions, are to be adjudicated upon by the Commission. Therefore, it has been deemed appropriate that a Judge of High Court should also be considered for appointment as a member and Chairman of the Commission. Further, in order to ensure effective functioning of the Commission, the upper cap of 65 years of age, as provided in clause (iv) of sub-section (1) of Section-46, should be removed.

A legislation i.e. 'The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Bill, 2024' to provide for appointment of a Judge of High Court as Members and Chairman of Commission and to remove the upper cap of 65 years of age and for matters connected therewith or incidental thereto, is required. Hence, this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 8th November, 2024.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2024 का विधेयक संख्या 19 एच.एल.ए.

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2014
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। | <p>1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।</p> <p>(2) यह 14 अक्टूबर, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।</p> |
| 2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 46 का संशोधन। | <p>2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 46 की उप-धारा (1) में,—</p> <p>(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>“(i) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश है या था, जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी अधिवर्षिता पर कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो;”;</p> <p>(II) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>“(iv) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, और यदि जिला न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक या तो सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष होगी :”।</p> |
| निरसन तथा व्यावृत्ति। | <p>3. (1) हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।</p> <p>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।</p> |

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

चूंकि, हरियाणा राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्ति के स्वायत्त प्रबंधन और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों से राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) अधिनियम, 2014 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 46 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है जिसमें तीन सदस्य होंगे और अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश होगा, यदि इस प्रकार नियुक्त किया जाता है और यदि जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है तो तीन सदस्यों में से एक उनकी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, होगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। गुरुद्वारा संपत्ति, उसकी निधियों और गुरुद्वारा समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्थानों के बीच किसी भी अन्य विवाद से संबंधित विवाद पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसलिए, यह उचित समझा गया है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, धारा-46 की उप-धारा (1) के खंड (iv) में प्रदान की गई 65 वर्ष की आयु की ऊपरी सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।

आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने और 65 वर्ष की आयु की ऊपरी सीमा को हटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक विधि अर्थात् हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, 2024 आपेक्षित है। अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 8 नवम्बर, 2024.

डॉ. सतीश कुमार,
सचिव।